डरबन वार्ता से नहीं निकलेंगे ठोस नतीजे

नई दिल्ली (एसएनबी)। डरबन में इस साल होने वाली जलवायु वार्ता से भारत को उत्सर्जन में कमी लाने सहित चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी ठोस और अंतिम घोषणा की उम्मीद नहीं है ।

टेरी द्वारा आयोजित 'दिल्ली सतत विकास सम्मेलन 2011' के एक सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं कि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें चर्चा और एक दूसरे का मत नहीं लेना चाहिए। कानकुन सम्मेलन से डरबन सम्मेलन तक के सफर के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, कि हमें यह बात साफ साफ समझनी होगी कि इन मुद्दों पर हमें अंतिम घोषणा मिलने नहीं जा रही है। वे तब भी एजेंडे में होंगे । उन पर चर्चा होगी और जैसा कि मैंने कहा कि डरबन में आखिरी घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डरबन जलवायु सम्मेलन के लिए उनका रूख यथार्थवादी है। रमेश ने कहा, अगर हम ज्यादा उम्मीद करेंगे तो हमें एक और निराशा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, उत्सर्जन में कमी के लिये कानूनी तौर पर बाध्यकारी क्योटो प्रोटोकॉल और कमी के लिये निर्धारित साल और तापमान वृद्धि के लिये वैश्विक लक्ष्य में दो डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री के बीच विवाद पर मैं कोई समझौता होता नहीं देख रहा हूं।

▶ 'हमें यह बात समझनी होगी कि इन मुद्दों पर हमें अंतिम घोषणा मिलने नहीं जा रही है'

▶ 'पर्यावरण के लिहाज से कानकुन निराशाजनक रहा पर राजनीतिक तौर पर यह एक आगे बढ़ा कदम'

जयराम ने कहा कि कानकुन सम्मेलन में जहां राष्ट्र कोपेनहगेन की असफलता से निराश होकर मिले जबकि उसके उलट इस समय पिछले अक्तूबर में नागाया में हुये सम्मेलन में मिली दो बड़ी सफलताओं की पृष्ठभूमि में वे मिल रहे थे । रमेश ने कहा, अगर आप मुझसे पर्यावरण के लिहाज से पूछेंगे तो कानकुन निराशाजनक रहा लेकिन राजनीतिक तौर पर यह आगे की ओर बढ़ाया एक कदम था।

पिछले साल कानकुन में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन देशों के समूह (बेसिक) द्वारा स्वीकार किये मसौदे पर बोलीविया की आलोचना को स्वीकार करने वाले अपने बयान पर बने रहते हुये उन्होंने कहा कि उनका 'दिल अब भी बोलीविया के साथ है लेकिन 'दिमाग' नहीं । जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये दीर्घकालिक कार्रवाई और क्योटो प्रोटोकाल पर 200 देशों के जलवायु वार्ताकारों द्वारा बनाये गये दो मसौदे पत्र पर बेसिक देशों ने खुशी जाहिर की थी। बोलीविया ने हालांकि मसौदे की आलोचना कर इसे बेहद कमजोर बताया था और दूसरे देशों पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता में उसे अलग करने का आरोप लगाया था।

...नहीं तो अगली पीढ़ी भुगतेगी

केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिये सभी देशों को 'ईमानदार नजरिया अपनाने की जरूरत है, अन्यथा बाकी कोशिशें वक्त की बर्बादी की तरह होंगी।

विकास की कीमत पर न हो संरक्षण

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि पर्यावरण संरक्षण विकास की कीमत पर नहीं होना चाहिये। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिये उचित नियम बनाने का कल पक्ष लिया था और कहा था कि यह सुनिश्चित होना चाहिये कि लाइसेंस राज की व्यवस्था दोबारा नहीं लौटे।